भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2352

गुरुवार, 20 मार्च, 2025/29 फाल्गुन, 1946 (शक)

देश में बेरोजगारी की समस्या

2352. डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत की बेरोजगारी की चुनौतियों पर प्रकाश डालने वाली हालिया रिपोर्टों, जिनमें दिसंबर 2024 में बेरोजगारी दर 7.8% बताई गई है, के आलोक में सरकार इस मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और
(ख) मांग में कमी हो जाने के कारण विनिर्माण गतिविधि वृद्धि में 14 महीने के निम्न स्तर को देखते हुए, विशेष रूप से युवाओं और ग्रामीण आबादी के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए क्या विशिष्ट नीतियां और पहल लागू की जा रही हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ख): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लिए सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 के दौरान 6.0% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएँ) डेटाबेस अखिल भारतीय स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र सहित रोजगार अनुमान प्रदान करता है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार वर्ष 2021-22 में 6.1 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 6.3 करोड़ हो गया है, जो इस अवधि के दौरान 20.27 लाख की वृद्धि दर्शाता है।

युवाओं एवं ग्रामीण जनसंख्या सहित सभी के लिए रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****